बृहस्पतिवार

33 साल से देहरादून का विश्वास

20 नवम्बर 2025

- देहरादून
- वर्ष 33
- अंक 286
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹1.00

दूनवैलीमेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली सीएम पद की शपथ

हमारे संवाददाता

पटना। पटना का गांधी मैदान में आज उत्साह का माहौल नजर आया। यहां ऐतिहासिक समारोह के बीच नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। व्यापक जनसमर्थन, देशभर के नेताओं की उपस्थिति और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह क्षण बिहार की राजनीति में एक बार फिर नया अध्याय जोड़ जोड़ गया है।

राज्यपाल ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके बाद उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन की नई सरकार ने औपचारिक रूप से कामकाज की शुरुआत कर दी। समारोह में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें पहली बार मंत्री बनने वाली जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह भी शामिल रहीं।

पटना के गांधी मैदान में आज सुबह से ही भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग विभिन्न जिलों से पटना पहुंचे और माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा दिखा। जगह-जगह 'जय बिहार', 'नीतीश कुमार जिंदाबाद' जैसे नारे गूंजते रहे। समर्थकों ने गमछे हवा में लहराकर नेताओं का अभिवादन किया। इस शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। बिहार के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित रहे। पीएम मोदी की मौजूदगी ने समारोह की गरिमा और राजनीतिक महत्व को कई गुना बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री के अलावा असम, हरियाणा, नागालैंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सहित 16 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक माहौल भी चरम पर रहा। मंच से छठ गीतों और भोजपुरी संगीत ने लोगों को लगातार ऊर्जा दी। मनोज तिवारी और पवन सिंह जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने भीड़ में अलग उत्साह पैदा किया।

कार्यक्रम का संचालन बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन ने किया, जिन्होंने पूरे संयम और जोश के साथ मंच गतिविधियों को संभाला। आज का यह शपथ ग्रहण सिर्फ एक औपचारिक घटना नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा, नेतृत्व में स्थिरता और भविष्य की नई उम्मीदों का प्रतीक बन गया। शपथ ग्रहण समारोह में जिन मत्रियों ने शपथ ग्रहण की उनके नाम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय चौधरी, विजेन्द्र यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन साहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन, सुनील कुमार, मो जमां खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेन्द्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेन्द्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, डा प्रमोद कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह व दीपक प्रकाश शामिल है।

दहेज हत्या प्रकरण पर महिला आयोग सख्त, पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश

संवाददाता

देहरादून। दहेज हत्या के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कडा रूख अपनाते हुए सीओ ऋषिकेश व एडिशनल एसपी को तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। आज यहां दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक गंभीर मामले में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सीओ ऋषिकेश डॉ. पूर्णिमा गर्ग और एडिशनल एसपी जया बलूनी को तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस को मामले की गंभीर जांच कर दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

शिकायत पत्र के अनुसार, ऋषिकेश निवासी उमेश कुमार ने अपनी पुत्री सोनी की दहेज उत्पीड़न और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुत्री की शादी 02 जुलाई 2023 को सुमित पुत्र विनोद निवासी जाटव बस्ती, रेलवे रोड, ऋषिकेश से हुई थी। शादी के शुरुआत से ही पुत्री को उसके पति व ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। इस संबंध में 30 सितंबर 2023 को थाना पुलिस को तहरीर भी दी गई थी। पीड़ित पिता के अनुसार 18 नवंबर 2025 की शाम करीब 6 बजे पुत्री के ससुराल वालों पति सुमित, सास जसवंती, ससुर विनोद, जेठ अमित, जेठानी रूबी, ननद कामिनी, शिया सहित अन्य रिश्तेदार ने मिलकर सोनी की हत्या कर दी। आरोप है कि घटना के बाद सभी आरोपी शव को सरकारी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। गंभीर आरोपों को देखते हुए महिला आयोग ने इसे अत्यंत संवेदनशील मामला मानते हुए पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए और दोषियों को कानूनन कठोर सजा दिलाई जाए। आयोग का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले ऐसे अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

लूट का खुलासा, चार बदमाश गिरफ्तार, लूटी गयी नगदी बरामद

हमारे संवाददाता

देहरादून। लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से लूटी गयी नगदी बरामद की गयी है। आरोपी नशे के आदी है जो नशापूर्ति के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे।

जानकारी के अनुसार बीते 18 नवम्बर को गुलाम रसूल पुत्र माम हसन, निवासी सात मोड गिजरेडा थाना ऋषिकेश जनपद देहरादून द्वारा कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर देकर बताया गया था कि 17 नवम्बर को वह ऋषिकेश क्षेत्र मे दूध बेचकर सरकारी अस्पताल के पास बाल्मिकी बस्ती रोड पर सडक किनारे बैठकर दूध से प्राप्त पैसो को गिन रहा थे, तभी अचानक चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मारपीट करते हुए उनके हाथ से पर्स व 10 हजार रूपये छीनकर भाग गये। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लुटेरो की तलाश शुरू कर दी गयी। लुटेरो की तलाश में जुटी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बीती रात उक्त लूट में शामिल चार लोगों अमन भण्डारी पुत्र पूरव सिंह भण्डारी, कैलाश पुत्र कुन्दन सिह, पंकज सिह पुत्र स्व. राजेन्द्र सिह व आकाश उर्फ गोलू पुत्र श्री आन्नाद मणी को एम्स जाने वाली रोड कोतवाली ऋषिकेश से लूटे गये 10 हजार रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। जिन्होने पूछताछ में बताया कि वह सभी दोस्त है तथा नशे के आदि है, नशे की पूर्ति के लिये उनके द्वारा आते जाते लोगो से सामान,मोबाइल व रूपये छीनाझपटी करते है।

दिनांक 17-11-2025 को उन्होने सरकारी अस्पताल के पास बाल्मिकी बस्ती रोड पर सडक किनारे एक व्यक्ति से 10 हजार रूपये छीनकर मौके से फरार हो गये थे। पुलिस क अनुसार आरोपी पूर्व मे भी विभिन्न अपराधो मे संलिप्त रहे है जिनके खिलाफ कई मुकदमें दर्ज है।

दून वैली मेल

संपादकीय

चुनावी जीत ही राजनीति

अगर राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव होता है और किसी भी नेता तथा राजनीतिक दल की सफलता का मापदंड चुनावी जीत ही है तब देश के लोगों को इस बात को स्वीकार करने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि देश को प्रधानमंत्री मोदी से और बेहतर नेता तथा भाजपा से अधिक अनुशासित कोई राजनीतिक दल न मिला है और न ही मिल सकता है। लेकिन यह विडंबना ही कही जा सकती है कि देश के आम आदमी से लेकर किसी भी राजनीतिक दल के नेता को भाजपा के चुनाव जीतने पर सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र की ही बू आती दिख रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव तक कभी भी किसी भी चुनाव को लेकर वैसा जन अविश्वास नहीं देखा गया था जैसा कि वर्तमान दौर में देखा जा रहा है। जनता के बीच वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों की सिर्फ अनुगूंज ही सुनाई नहीं दे रही है अपितु हर तरफ वोट चोरी से चुनाव जीतने के मुद्दे की चर्चाएं आम है। अगर इन चर्चाओं को कोई बेवजह मानता है तो यह गलत ही है। इन संभावनाओं को बल बेवजह नहीं मिला है। 2024 के चुनाव में भाजपा के नेताओं द्वारा जो अबकी बार 400 पार का नारा दिया गया था वह भले ही धरातल पर सच से कोसों दूर रह गया सही लेकिन भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने और विपक्ष रहित सरकार बनाने के दावे भी बेवजह नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार विपक्ष को दर्शक दीर्घा में बैठे नजर आने की चेतावनी दे चुके हैं। भाजपा के नेता आज अगर हर एक चुनाव से पूर्व बड़ी बेफिक्री के साथ यह कहते देखे जा रहे हैं कि विपक्ष चाहे जो भी कुछ कर ले जीतेगी बीजेपी ही इसे वह सिर्फ कह नहीं रहे हैं बल्कि अब धरातल पर हो भी यही रहा है। बात चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव की हो या फिर हरियाणा और बिहार के चुनाव की अब भाजपा को चुनाव के मैदान में कोई नहीं हरा सकता है और चुनाव परिणाम वैसे ही रहने वाले हैं जैसे की बिहार चुनाव में हुआ है। जहां भाजपा और जेडीयू ने लगभग बाकी सभी दलों का सुपड़ा ही साफ कर डाला है तो यह स्वाभाविक ही है कि किसी भी दल को चुनाव लड़ने की जरूरत ही क्या रह जाती है चुनाव तो इसीलिए लड़ा जाता है कि हम जीते भी सकते हैं। लेकिन जब पहले से यह पता हो कि हमें तो हारना ही है तो हारने के लिए क्यों कोई चुनाव लड़ेगा इस चुनावी हार के पीछे अब तमाम तरह के कारण जरूर खोज लिए गए हैं लेकिन इनका जवाब न निर्वाचन आयोग देने को तैयार है और न देश की अदालतें इस मुद्दे पर कोई प्रभावी कार्यवाही कर पा रही हैं। ऐसी स्थिति में अब विपक्ष और आम आदमी के पास सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सोशल मीडिया पर विपक्ष के इस फैसले के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है। विपक्ष पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को समाप्त करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं। कई बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वह चुनाव नहीं हारे तो अब प्रधानमंत्री रहते हुए भी चुनाव नहीं हारे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वह भाजपा के सबसे बड़े प्रचार मंत्री के तौर पर अभी इतने सक्रिय है कि हर चुनाव में उनकी सबसे अधिक जनसभाएं होती है। शायद इस तरह का प्रचार करने वाले वह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो उतने ही बड़े अविश्वास से घिरे हैं कि उनकी जीत पर अब किसी का भी भरोसा नहीं रहा है।

युवती से छेडछाड गाली गलौच करने पर आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा

देहरादून(संवाददाता)। युवती से छेडछाड करने व विरोध करने पर गाली गलौच करने के मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवास विकास कालोनी भरत विहार निवासी युवती ने ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह घर की तरफ आ रही थी तभी रास्ते में उसको मौहल्ले के ही हाशिम उर्फ सोनू, अब्बास, इस्लाम व उनके अन्य साथियों ने छेडछाड करनी शुरू कर दी। उसने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ गाली गलौच करते हुए धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। जब आसपास के लोग वहां पर पहुंचे तो सभी वहां से भाग गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

विदेश में पढाने के नाम पर ठगे पांच लाख रूपये

देहरादून(संवाददाता)। विदेश में पढाने के नाम पर पांच लाख रूपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकाश नगर ईदगाह निवासी ऋचा वर्मा ने कैण्ट कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि रविन्द्र पुरी सालावाला निवासी प्रशान्त वर्मा ने उसके बेटे को विदेश में पढाई के लिए उनकी अनुमति के बिना नॉन बैंकिग फाईनेंन्स कम्पनी से पांच लाख 15 हजार रूपये का लोन उनके नाम से लेकर हडप लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

विदेश में नौकरी के नाम पर ठगे सवा तीन लाख रूपये

देहरादून(संवाददाता)। विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर सवा तीन लाख रूपये की ठगी करने के मामले में तीन लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय पार्क एक्सटेंशन निवासी अनुप सिंह ने नेहरू कालोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पहचान नेहरू ग्राम निवासी अरूण कुमार थापा से हुई। अरूण ने उसकी पहचान रणवीर सिंह यादव व राजकुमार से करायी। जिन्होंने उसको विदेश में नौकरी का झांसा देकर उससे सवा तीन लाख रूपये ठग लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत

पटना(हमारे संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पटना आगमन पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने परंपरागत तरीके से पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री धामी ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनके स्नेह और सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री का आगमन उनके लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है।

उपनल कर्मियों का धरना 11वें दिन भी जारी

संवाददाता

देहरादून। नियमितीकरण व समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर धरना 11वें दिन भी जारी रहा।

आज यहां नियमितीकरण व समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर उपनल कर्मियों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। संगठन के संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के आंदोलन में शही हुई बहन नीलम डोभाल की दुखद घटना होने पर भी सरकार का कोई मंत्री या अधिकारी धरना स्थल पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने नहीं आया। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे मंत्री और अधिकारी शायद अभी और कर्मचारियों के बलिदान हाने का इंतजार कर रहे है। धरने पर हरीश कोठारी, महासंघ के प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेश भटट, प्रदीप सिंह, भूपेश नेगी, गणेश गोदियाल, सहित दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे।

लघु व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग ने किया जागरूक

संवाददाता

हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लघु व्यापारियों को जागरूक करते हुए नियमों की जानकारी दी। आज यहां उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को जागरुक करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के नियमों की जानकारी को लेकर प्रथम वेंडिंग जोन के प्रांगण में एक दिवसीय जन जागरण अभियान का शुभारंभ करते हुए नगर निगम खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा ने विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ आगामी 28 नवंबर को प्रशिक्षण लाईसेंस वितरण कार्यक्रम के साथ रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई। इस अवसर पर हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा ने कहा राज्य सरकार के निर्देशन में रेड़ी पटरी के माध्यम से खाने-पीने की वस्तु का व्यापार संचालित करने वाले सभी रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को प्रशिक्षित कर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने के लिए यह जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि आगामी 28 नवंबर को ऋषि कुल के सभागार में लघु व्यापारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण का अभ्यास कराया जाएगा और खाद्य सुरक्षा के नियमों की जानकारी के साथ फुटपाथ पर खाने-पीने की वस्तु बेचने वाले सभी लघु व्यापारियों के पंजीकरण भी विभाग द्वारा किए जाएंगे। इस अवसर पर लघु व्यापार एसो.के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा काफी समय से फुटपाथ पर खाने-पीने की वस्तु बेचने वाले लघु व्यापारियों की खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पंजीकरण की मांग की जा रही थी जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के संयुक्त नेतृत्व में हरिद्वार जिले में प्रथम बार रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों की जानकारी के साथ जागरूकता के इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत योजना के तहत अर्ध कुंभ मेले से पहले सभी सार्वजनिक स्थलों के निकट फुटपाथ के भोजनालय बाजार बनाकर वेंडिंग जोन को व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की सार्थक पहल भी को किया जाना उचित होगा।

कब-कब नीतीश कुमार ने ली है सीएम पद की शपथ, उनके साथ कौन रहे हैं उपमुख्यमंत्री

पटना। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 19 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, ठश्रच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और छक। के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। बुधवार को, नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर नई सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के सामने दावा पेश किया।

एनडीए के मुख्य घटक दलों, BJP और JD(U) को कैबिनेट सीटों के अलावा, गठबंधन के अन्य सहयोगियों को भी संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हर छह डस। पर एक मंत्री पद मिलने की संभावना है। नई बनी विधानसभा का तीन दिन का सेशन 26 नवंबर से शुरू होगा जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे और नए सदस्य शपथ लेंगे।

बिहार में छक। ने 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की, जिसमें BJP को 89, JD(U) को 85, LJP(RV) को 19, HAM(S) को 5 और RLM को 4 सीटें मिलीं।

नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उपमुख्यमंत्री बने, जो उनके राजनीतिक कौशल और गठबंधन बनाने की क्षमता को दर्शाता है। यह शपथ ग्रहण समारोह बिहार की राजनीतिक स्थिरता और एनडीए के बढ़ते प्रभाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2020 में शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं लिया था। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ, जहाँ 2005, 2010 और 2015 में उनके शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो चुके हैं। यहीं पर जयप्रकाश नारायण ने 1974 में एक भाषण के दौरान संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। एनडीए शासित राज्यों के विभिन्न मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अपने सभी कार्यकालों में, नीतीश कुमार ने विकास के मुद्दों को लगातार प्राथमिकता दी है, बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और कानून-व्यवस्था में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका बिहार के शासन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुल मिलाकर, नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा प्रभावी गठबंधन निर्माण, बदलती राजनीतिक गतिशीलता के अनुकूल ढलने की क्षमता और बिहार की प्रगति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से चिह्नित है, जिसने उन्हें राज्य के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया है। राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले इस नेता का राजनीतिक सफर 1985 में पहली बार राज्य विध ानसभा में प्रवेश करने के बाद से काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने अपना करियर जनता दल से शुरू किया और 1989 में लालू प्रसाद यादव को विपक्ष का नेता चुने जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, जल्द ही उनका यादव से मतभेद हो गया और उन्होंने 1994 में जनता दल (जॉर्ज) नामक एक अलग गुट बनाने में मदद की, जो बाद में समता पार्टी बन गया।

-1996 में, कुमार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए और 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल, भूतल परिवहन और कृषि मंत्री रहे। वह 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत की कमी के कारण केवल सात दिनों के बाद ही इस्तीफा दे दिया।

दूसरा शपथ- 2005

-2005 के विधानसभा चुनावों के बाद, नीतीश ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इस बार एनडीए के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन का नेतृत्व करते हुए। इस कार्यकाल ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के उनके प्रयासों की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा के सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री रहे।

तीसरी शपथ - नवंबर 2010-2014

कुमार की सरकार ने साइकिल और भोजन कार्यक्रम भी शुरू किए। नीतीश 2010 के विधानसभा चुनावों में फिर से निर्वाचित हुए और तीसरी बार शपथ ली। उनकी एनडीए सरकार ने शासन सुधारों, सड़क विकास और सामाजिक पहलों पर जोर देते हुए सत्ता को मजबूत करना जारी रखा। सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री रहे। 2014 के लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के एक दिन बाद, 17 मई 2014 को, कुमार ने बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

चौथी शपथ - 22 फरवरी, 2015

जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, नीतीश ने चौथी बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

पाँचवीं शपथ - नवंबर 2015-2017

2015 में, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाने के बाद, नीतीश ने फिर से शपथ ली। इस कार्यकाल में भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए उनके रणनीतिक बदलाव को दर्शाया गया और गठबंधन को निर्णायक जनादेश मिला। राजद नेता तेजस्वी यादव इस दौरान उपमुख्यमंत्री रहे।

छठी शपथ - जुलाई 2017-2020

जुलाई 2017 में, नीतीश ने राजद नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देते हुए महागठबंधन से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे एनडीए में शामिल हो गए और छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिससे एक नाटकीय राजनीतिक बदलाव आया और वे भाजपा के पाले में लौट आए। इस दौरान सुशील कुमार मोदी फिर से उपमुख्यमंत्री रहे।

सातवीं शपथ - नवंबर 2020

2020 के विधानसभा चुनावों के बाद, नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार के हिस्से के रूप में सातवीं बार शपथ ली। उनके गठबंधन ने शासन, विकास परियोजनाओं और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। इस दौरा तारकिशोर प्रसाद और रेणू देवी उपमुख्यमंत्री रहे।

आठवीं शपथ - अगस्त 2022

अगस्त 2022 में, बिहार के एनडीए गठबंधन में आंतरिक मतभेदों और राजनीतिक फेरबदल के बाद, नीतीश ने राजद के समर्थन से एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इस बार तेजस्वी यादव उनके उप-मुख्यमंत्री बने। यह कार्यकाल राज्य की राजनीति में उनके निरंतर प्रभुत्व और बदलते गठबंधनों को साधने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। तेजस्वी यादव इस दौरान उपमुख्यमंत्री रहे।

नौवीं शपथ - जनवरी 2024

नीतीश कुमार ने नौवीं शपथ जनवरी 2024 में ली, 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले, राजद-जद(यू) सरकार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद। इस बार उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन किया। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नीतीश के साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

राहुल के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स का पत्र

कहा, चुनाव आयोग की छवि खराब कर रही कांग्रेस

नई दिल्ली। चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देशभर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया है। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई है। लेटर में 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट (14 पूर्व राजदूत सहित) और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। इन रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने ओपन लेटर में आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है।

पत्र में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है। उस पर बार-बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक मतभेद जरूरी हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाना देशहित के खिलाफ है। दरअसल, राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप में अब तक तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने आयोग को मोदी सरकार की टीम भी कहा था। भाजपा के साथ वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। पत्र के अनुसार, बिना सबूत के लगाए जाने वाले आरोप एक क्रोध का रूप हैं, ऐसा गुस्सा जो बार-बार चुनावी हार और जनता से दूरी के कारण पैदा हुआ है। पत्र में आगे कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दल विश्लेषण की जगह नाटकीयता को चुन रहे हैं और सार्वजनिक सेवा की जगह राजनीतिक तमाशा कर रहे हैं। देश की इन हस्तियों ने लिखा कि जब किसी विपक्ष शासित राज्य में चुनाव आयोग के परिणाम विपक्ष के अनुकूल होते हैं, तब उसकी आलोचना गायब हो जाती है। लेकिन जब परिणाम उनके खिलाफआते हैं, तब आयोग को हर कहानी का खलनायक बना दिया जाता है। उन्हें यह चुनिंगा नाराजगी राजनीतिक अवसरवाद का उदाहरण लगी। इस खुले पत्र में टीएन शेषन और एन गोपालस्वामी जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उन्होंने लोकप्रियता या सुर्खियों के बजाय निष्पक्षता और कड़ाई से नियमों का पालन कराया। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि भारत की संस्थाओं को राजनीतिक हमलों का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, यही परंपरा देश को मजबूत बनाती है।

वरिष्ठ नागरिकों ने चुनाव आयोग से कहा कि वह पारदर्शिता बनाए रखे, सभी आंकड़े सार्वजनिक करे और आवश्यक होने पर कानूनी तरीकों से अपना बचाव करे। इसके साथ ही राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे बिना सबूत वाले आरोपों की जगह नीतिगत विकल्प और देश के लिए ठोस दृष्टि पेश करें। वहीं इस पत्र के आखिरी में देश की वरिष्ठ हस्तियों ने भारतीय सेना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विशेष रूप से चुनाव आयोग पर अपना अटूट विश्वास जताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और अब समय आ गया है कि राजनीति नाटकीयता नहीं, बल्कि सत्य, विचार और सेवा के आधार पर आगे बढ़े।

आतंकी डॉ. उमर तैयार कर रहा था सुसाइड बॉम्बर

नई दिल्ली। लाल किले के सामने विस्फोटक से भरी कार उड़ाने वाला आतंकी डॉ. उमर नबी अपने जैसे कई और सुसाइडल बॉम्बर तैयार करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए वह लगातार वीडियो बनाकर युवाओं को भेजता था, ताकि उनका ब्रेनवॉश किया जा सके। जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है।

सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन में डॉ. उमर के 12 वीडियो समेत 70 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। ऐसे ही वीडियो 11 लोगों को भेजे गए थे। इनमें से 7 युवा कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं और सभी का अल-फ्लाह यूनिवर्सिटी से लिंक मिला है। बाकी 4 युवा उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के रहने वाले हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आमिर रशीद अली, जिसने उमर नबी को आई-20 कार दिलवाई थी, खुद सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार नहीं था। इसके बाद उमर ने उसे भी ऐसे ही ब्रेनवॉश करने वाले वीडियो भेजे थे। एजेंसियों को शक है कि उमर नबी एक पूरी फ्दायीन टीम तैयार कर रहा था और उसका टारगेट कई राज्यों के युवा थे।

दिल्ली ब्लास्ट से पहले पुलवामा गया था आतंकी उमर

दिल्ली कार ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाला आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद हमले से करीब 2 हफ्ते पहले पुलवामा के कोइल गांव में अपने घर गया था। उमर ने अपने दो मोबाइल फोन में से एक अपने भाई जहूर इलाही को दिया और कहा कि अगर मेरे कोई खबर आए तो फोन पानी में फेंक देना। इसी फोन से वह वीडियो मिला है, जिसमें उमर आत्मघाती हमले को शहादत का ऑपरेशन बता रहा है। जहूर ने सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में फोन के बारे में जानकारी दी है। जहूर ने बताया कि उमर ने उसे 26 से 29 अक्टूबर के बीच फोन दिया था। 9 नवंबर को अल-फ्लाह यूनिवर्सिटी से उमर के साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उसने घबराकर फोन घर के पास एक तालाब में फेंक दिया था। जांच एजेंसियों ने 9 नवंबर को उमर के दोनों फोन तलाशे तो दोनों बंद मिले थे। एक फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली और दूसरे की पुलवामा थी।

जब डॉक्टर ही निकले जूता-बम विस्फोट के आतंकी!

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर, यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इस काम के लिए ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इकोस्पोर्ट और आई20 जैसी गाड़ियां शामिल की गई थीं। पुलिस की जांच एजेंसियों को अब तक 3 कारें बरामद हो चुकी हैं,जबकि चौथी चौथी स्विफ्ट डिजायर की तलाश है। बीती 10 नवंबर को जिस आई20 कार में जूता- बम धमाका हुआ था, वह इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है।यह विस्फोट जूता बम से किया गया,यह एनआईए की चल रही जांच में खुलासा हुआ है। जूता -बम बेहद खतरनाक माना जाता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में टेरर अटैक पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। पुलिस ने हरियाणा के खंदावली गांव से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। यहीं से इको स्पोर्ट्स कार बरामद हुई है।पुलिस ने आशंका जताई कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं, बल्कि दो कारें थीं। जिसकी तलाश के लिए दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्यों यूपी और हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद हरियाणा के खंदावली गांव में लावारिस गाड़ी होने की खबर सामने आई। इस गाड़ी की जांच के लिए एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची है। गाड़ी अभी तक पूरी तरह से खोली नहीं गई है। गाड़ी जहां मिली, वह उमर के ड्राइवर की बहन का घर था।दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस का मानना है कि आतंकियों द्वारा बीती जनवरी में लाल किले की रेकी की गई थी।यानि दिल्ली को दहलाने की साजिश जनवरी से रची जा रही थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल डंप डेटा से पता चला कि फरीदाबाद की अल फ्लाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मुजम्मिल गनी और धमाके में कथित रूप से मारे गए डॉ. उमर नबी ने जनवरी में कई बार लाल किले की रेकी की थी। दोनों ने वहां की सुरक्षा-और भीड़ का पैटर्न समझा था। पुलिस को शक है कि आतंकियों की प्लानिंग 26 जनवरी पर लाल किले पर हमले की थी, जो उस समय नाकाम हो गई थी।साथ ही दिल्ली में 6 दिसंबर को आतंकियों का हमले करने का प्लान था , लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी से उनका प्लान बिगड़ गया। यह बात 8 आरोपियों से पूछताछ में भी सामने आई हैं। इस अंतरराज्यीय मॉड्यूल का केंद्र फरीदाबाद में था। गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। श्रीनगर का रहने वाला एक अन्य संदिग्ध डॉ. निसार फरार है,जो डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है,वह अलफ्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था।इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने डॉ. निसार को बर्खास्त कर दिया है।वही गनी नामक आतंकी खाद की बोरी बताकर विस्फोटक जुटा रहा था। फरीदाबाद की अल फ्लाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा कश्मीरी डॉ. मुजम्मिल गनी खाद की बोरियां बताकर किराए के कमरे में विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। 20 दिन पहले मुजम्मिल कमरे में कुछ बोरियां रखने आया था, तब पड़ोसियों ने उससे पूछा था कि इसमें क्या है? जवाब में मुजम्मिल ने कहा था कि ये खाद के कट्टे हैं। इन्हें कश्मीर ले जाना है।पुलिस ने विस्फोटक रखे कमरे से 100 मीटर दूर एक मकान में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब्त कर ली हैं।दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एटीएस ने कानपुर के कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर आरिफ को भी गिरफ्तार किया है। उसका कनेक्शन मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर और उसकी सहयोगी लेडी टेररिस्ट डॉ. शाहीन से मिला है। आरिफ दोनों लोगों के संपर्क में था। जांच में यह भी सामने आया कि शाहीन और आरिफ के बीच हर रोज बात होती थी।जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सोपोर के मूमिनाबाद इलाके में संयुक्त अभियान के दौरान दो हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान शबीर नजार और शबीर मीर के रूप में हुई है।कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार, आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। फ्लिहाल पूरे मामले की जांच जारी है और सुरक्षाबल यह पता लगाने में जुटे हैं कि दोनों की आतंकी नेटवर्क से कितनी गहरी संलिप्तता थी

पुलिस ने हरियाणा के खंदावली गांव से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। यहीं से इको स्पोर्ट्स कार बरामद हुई है।वही दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एटीएस ने कानपुर के कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर आरिफ को अरेस्ट किया है। उसका कनेक्शन मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर और उसकी सहयोगी लेडी टेररिस्ट डॉ. शाहीन से मिला है। आरिफ दोनों लोगों के संपर्क में था। जांच में यह भी सामने आया कि शाहीन और आरिफ के बीच हर रोज बात होती थी।जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सोपोर के मूमिनाबाद इलाके में संयुक्त अभियान के दौरान दो हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान शबीर नजार और शबीर मीर के रूप में हुई है।कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार, आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। फ्लिहाल पूरे मामले की जांच जारी है और सुरक्षाबल यह पता लगाने में जुटे हैं कि दोनों की आतंकी नेटवर्क से कितनी गहरी संलिप्तता थी

कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार, आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। फ्लिहाल पूरे मामले की जांच जारी है और सुरक्षाबल यह पता लगाने में जुटे हैं कि दोनों की आतंकी नेटवर्क से कितनी गहरी संलिप्तता थी।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर हाई लेवल की मीटिंग हुई। जिसमें दिल्ली पुलिस, एनआईए और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह जम्मू रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन किया गया जम्मू रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने संयुक्त रूप से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों ने बताया कि यह जांच यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई।गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाएगी, जिससे दुनिया को संदेश मिले कि भारत में ऐसा करने की हिम्मत कोई दोबारा न करे।उन्होंने ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि आतंकवाद के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, और यह संकल्प जरूर पूरा होगा। 24 घंटे के भीतर जम्मू-कश्मीर के रहने वाले दो डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। हापुड़ के मेडिकल कॉलेज से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फारुख को उसके हॉस्टल से पुलिस ने उठाया। फारुख ने फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल शकील के साथ पढ़ाई की है। मुजम्मिल के पास भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट से पहले उमर से सम्बंधित 6 सीसीटीवी भी सामने आए हैं। इसमें उमर 17 घंटे पहले हरियाणा के नूंह में दिखा,पुलिस को शक है कि उसने यहीं से विस्फोटक कार में रखे। कांग्रेस ने दिल्ली धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि जब उसकी नीति आतंकवाद पर 'जीरो टॉलरेंस' की है, तो 2,900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद तक कैसे पहुंच गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फरीदाबाद की अल फ्लाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉ. उमर उन नबी, डॉ. मुझम्मिल गनई और डॉ. शहीन शाहिद ने स्विट्जरलैंड के 'थ्रीमा' नाम के एन्क्रिप्टेड ऐप से बातचीत की थी। इसी ऐप के जरिए वे धमाके की पूरी योजना, नक्शे और दस्तावेज साझा कर रहे थे।थ्रीमा ऐप फोन नंबर या ईमेल के बिना काम करता है और हर यूजर को एक यूनिक आईडी देता है, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने अपना निजी सर्वर तैयार कर रखा था, जिस पर वे सुरक्षित तरीके से संवाद करते थे।सरकार ने अल फ्लाह यूनिवर्सिटी के सभी रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच (ऑडिट) कराने का फैसला किया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने अन्य एजेंसियों को भी अल फ्लाह यूनिवर्सिटी के पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) की जांच करने के निर्देश दिए हैं।दिल्ली पुलिस ने अल फ्लाह यूनिवर्सिटी के एच आर विभाग से जमील को गिरफ्तार किया है। जमील जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। उस पर आतंकियों का सहयोग करने का आरोप है। फ्लिहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर डॉ. उमर नबी के आखिरी 24 घंटे की पूरी मूवमेंट ट्रैक की। जांच में पता चला है कि वह 9 नवंबर की रात फरीदाबाद से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते निकला और हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में एक ढाबे पर रुका। वहीं उसने कार में ही रात गुजारी। अगली सुबह वह फिर एक्सप्रेसवे से होते हुए धीरे-धीरे दिल्ली की ओर आया। रास्ते में उसने दो बार रुककर चाय पी और फोन चेक किया।सीसीटीवी फुटेज में वह सुबह 8.13 बजे बादरपुर टोल पार करता दिखा। इसके बाद उसने ओखला, कनॉट प्लेस, अशोक विहार और सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में चक्कर लगाए। दोपहर में अशोक विहार में एक ढाबे पर खाना खाया, फिर वह रामलीला मैदान के पास असफअली रोड की एक मस्जिद गया, जहां उसने तीन घंटे तक कार पार्किंग में बिताए और नमाज पढ़ी। पुलिस को शक है कि इसी दौरान उसे अगले निर्देश मिले। 3.19 बजे उसकी सफेद हुंडई आई 20 कार को लाल किला पार्किंग में खड़ा देखा गया। कार करीब तीन घंटे तक वहीं रही। 6.22 बजे वह कार मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ी और 6.52 बजे जबरदस्त धमाके के साथ फट गई। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत और 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्र किए गए विस्फोटक के साथ फरीदाबाद से पकड़ी गई डॉ. शाहीन डेढ़ वर्ष से परिवार के संपर्क में नहीं थी। पूछताछ में शाहीन के पिता सईद अंसारी ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा शोएब है। डॉ. शाहीन दूसरे, जबकि डॉ. परवेज तीसरे नंबर पर हैं। लोकसेवा आयोग से चयनित होकर शाहीन कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर चुकी है। परिजनों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कुछ वर्ष काम करने के बाद वर्ष 2013 में बिना कोई नोटिस दिए शाहीन ने वहां जाना छोड़ दिया था। शाहीन की शादी महाराष्ट्र निवासी जफर हयात से हुई थी। आपसी विवाद के कारण वर्ष 2015 में दोनों अलग हो गए। उधर, अनुपस्थित रहने की वजह से वर्ष 2021 में मेडिकल कॉलेज ने डॉ. शाहीन को बर्खास्त कर दिया था। परवेज के घर के बाहर एक कार खड़ी मिली। कार पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास लगा था। छानबीन में पता चला कि परवेज वहां पर काम करता था। कार परवेज के भाई शोएब के नाम है, जो सहारनपुर में रजिस्टर्ड है। फरीदाबाद से बरामद कार परवेज के नाम रजिस्टर्ड है। करीब चार घंटे तक खुफिया एजेंसियों ने परवेज का घर खंगाला। एटीएस ने आस पड़ोस के लोगों से भी परवेज के बारे में जानकारी जुटाई है। माना जा रहा है कि परवेज को उसके साथियों के पकड़े जाने की भनक लग गई थी, जिसके बाद वह घर से भाग निकला था।

सवालों के घेरे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

विश्व राजनीति की अशांत मिट्टी पर खड़े संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नैतिक व संस्थागत आधार आज पहले से कहीं अधिक प्रश्नों से घिरा है। जब युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, तब शांति का सबसे बड़ा संरक्षक स्वयं अपनी भूमिका सिद्ध करने में असफल दिख रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1945-आधारित संरचना आज की बहुध्रुवीय और संघर्षग्रस्त दुनिया में शांति बनाए रखने में सक्षम नहीं रह गई है। वीटो शक्ति का राजनीतिक दुरुपयोग, अप्रतिनिधिक सदस्यता, कमजोर राजनीतिक निरंतरता, असंगठित शांति अभियानों और बड़े मानवीय संकटों पर निष्क्रियता ने च्छैब् को कठघरे में खड़ा कर दिया है। वैश्विक दक्षिण की बढ़ती असंतुष्टि और विश्व व्यवस्था में उभरते शक्ति-संतुलन इस संस्था की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाते हैं। संयुक्त राष्ट्र को अपनी वैधता और प्रभावशीलता बचाने के लिए गहरे, व्यावहारिक और कार्यात्मक सुधार अपनाने होंगेकृअन्यथा शांति का यह सबसे बड़ा संरक्षक स्वयं प्रश्नों का केंद्र बन जाएगा। सवालों के घेरे में खड़ा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद केवल एक संस्था का संकट नहीं है, बल्कि यह वैश्विक नैतिक नेतृत्व के क्षरण की बड़ी कहानी भी है। जब संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ था, तब दुनिया दूसरी विश्वयुद्ध की राख से निकल रही थी और मानवता ने सामूहिक रूप से यह प्रण लिया था कि भविष्य में किसी भी बड़े युद्ध को रोका जाएगा। उस सपने का केंद्र थाकृसुरक्षा परिषद, जिसे शांति का संरक्षक, वैश्विक न्याय का प्रहरी और सामूहिक सुरक्षा का आधार माना गया। मगर आज, लगभग 80 वर्ष बाद, जब दुनिया यूक्रेन, गाजा, सूडान, यमन, म्यांमार और साहेल जैसे संघर्षों से दहक रही है, तब यह संस्था अक्सर मौन खड़ी दिखाई देती है। यह मौन केवल असहायता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस संरचनात्मक कमजोरी का भी संकेत है जिसने वर्षों में इसकी विश्वसनीयता को खोखला कर दिया। जब दुनिया भर के नागरिक शांति की उम्मीद में इस संस्था की ओर देखते हैं, तब यह भू-राजनीतिक हितों की जकड़ में बंधी दिखाई देती है। यही कारण है कि आज शांति का सबसे बड़ा संरक्षक स्वयं सबसे बड़े सवालों का विषय बन गया है।

सबसे बड़ी समस्या हैकृवीटो शक्ति से पैदा होने वाला शक्ति-असंतुलन। पाँच स्थायी सदस्य देशों के हाथों में केंद्रित यह शक्ति उन्हें किसी भी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार देती है, भले वह प्रस्ताव मानवीय त्रासदी को रोकने जितना आवश्यक ही क्यों न हो। यही कारण है कि गाजा में हजारों बच्चों की मौतें हों, यूक्रेन में शहरों के शहर तबाह हो जाएँ, या म्यांमार में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विनाश होकृसुरक्षा परिषद अक्सर पक्षाघात की स्थिति में दिखाई देती है। यह एक ऐसे दरवाजे का दृश्य बन गया है जिसके बाहर सहायता की गुहार लगाने वाले लाखों लोग खड़े होते हैं, लेकिन उस दरवाजे को खोलने की चाबी कुछ सीमित देशों के हाथों में होती है, जो अपने राष्ट्रीय हितों को वैश्विक शांति से ऊपर रख देते हैं। सवाल यहाँ से आगे बढ़ता हैकृक्या शांति किसी राष्ट्र के हितों से छोटी हो सकती है? क्या हत्या और भूख से जूझते लोग किसी स्थायी सदस्य की भू-नीति के कारण मृत्यु के लिए छोड़ दिए जाएँ? क्या संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन का उद्देश्य केवल औपचारिक बयान देना रह गया है? ये प्रश्न आज तीखे होते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में मीडिया, नागरिक समाज और शांति विशेषज्ञ लगातार यह महसूस कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की नैतिक शक्ति का क्षरण हो चुका है।

दूसरी समस्या हैकृइस संस्था की संरचना का अप्रतिनिधिक होना। दुनिया 1945 से अब पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन यूएनएससी की संरचना लगभग जड़वत है। अफ्रीका, जो संघर्षों का केंद्र भी है और शांति के लिए सर्वाधिक योगदान भी देता है, उसका कोई स्थायी प्रतिनिधि नहीं है। भारत जैसा विशाल लोकतंत्र, जिसके योगदान शांति रखरखाव से लेकर मानवीय सहायता तक व्यापक हैं, उसे भी अब तक स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। यह एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था का संकेत है जो वास्तविकता से कट चुकी है। जहाँ वैश्विक शक्ति-मानचित्र बदल गया हैकृचीन का उदय हुआ, भारत आर्थिक व राजनीतिक रूप से नई ऊँचाइयों पर पहुँचा, अफ्रीका उभरती संभावनाओं का महाद्वीप बन गया, लातिन अमेरिका राजनीतिक रूप से अधिक मुखर हुआकृवहाँ सुरक्षा परिषद अब भी 1945 की मानसिकता में फंसी है। परिणामस्वरूप, कई देश इसे वैध के बजाय केवल पुरानी व्यवस्था का अवशेष समझने लगे हैं। तीसरी समस्या हैकृशांति अभियानों की राजनीतिक विफलता। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों ने कई जगह हिंसा को रोका जरूर, परंतु राजनीतिक स्थिरता नहीं ला सके। यह ऐसा था मानो किसी टूटते हुए घर की दीवार पर रंग तो कर दिया जाए, लेकिन दरारों की मरम्मत न की जाए। शांति केवल बंदूकें शांत कर देने से नहीं आतीय यह आती है संवाद, समावेशन, शासन-सुधार और समाज के भीतर विश्वास पैदा करने से। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का तंत्र शांति स्थापना और राजनीतिक समाधान को एकीकृत नहीं कर पाता।

ऐथलीट्स कीटो डायट से करें परहेज, परफॉर्मेंस पर पड़ता है असर

एक नई रिसर्च के मुताबिक ऐथलीट्स को केटोजेनिक डायट जिसे कीटो डायट भी कहते हैं से परहेज करना चाहिए। इस स्टडी की मानें तो कीटो डायट जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बेहद कम और फैट की मात्रा अधिक होती है उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ता है। अनुसंधानकर्ताओं की मानें तो कीटो डायट से ऐथलीट्स की परफॉर्मेंस खराब क्यों हो जाती है, इसकी वजह का खुलासा नहीं हो पाया है लेकिन माना जाता है कि कीटो डायट की वजह से इंसान की अवायवीय यानी एनाईरोबिक एनर्जी पर असर पड़ता है।

फैट के टुकड़ों से मिलती है एनर्जी

किटॉसिस बॉडी की ऐसी मेटाबॉलिक सिचुएशन है, जिससे बॉडी कार्बोहाइड्रेट के बजाय फैट के टुकड़ों को तोड़कर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की गई 2018 की बेस्ट डायट लिस्ट में कीटो डायट को भी शामिल किया गया है।

क्या है कीटो डायट?

डायटिशन एकता तिवारी बताती हैं, जब

आप अपनी डायट में 1 दिन में 30 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट लेने लगते हैं तो आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट से मिली एनर्जी से अपना काम करने लगती है। यहां तक कि ब्रेन भी अपना काम इसी एनर्जी से चलाता है। इस डायट में कार्बोहाइड्रेट तो न के बराबर होता ही है, साथ ही शुगर की मात्रा भी 5 फीसदी से ज्यादा नहीं होती। इस डायट में हाई फैट, नॉर्मल प्रोटीन और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया जाता है।

भूख लगती है बेहद कम

आसान भाषा में इस डायट में ऐसा खाना खाया जाता है, जिसमें 70 से 80 प्रतिशत फैट, 10-20 प्रतिशत प्रोटीन और सिर्फ 5 प्रतिशत कार्ब्स होते हैं। इसको शुरू करने के 4 से 5 दिन बाद आपकी बॉडी किटॉसिस पर चली जाती है, जिससे भूख बेहद कम लगती है। एकता बताती हैं ग्लूकोज और प्रोटीन की सही मात्रा न मिलने की वजह से शरीर किटॉसिस प्रोसेस शुरू कर देता है, जिसमें बॉडी का फैट पिघलकर एनर्जी में तब्दील होता है। इस डायट की खासियत यह है कि कम खाने के बाद भी बॉडी मसल्स पर असर नहीं पड़ता है।

एक्सपर्ट की गाइडेंस जरूरी

कीटो डायट एक्सपर्ट की देखरेख में शुरू करें। एक बार बॉडी जब इसके लिए फिट हो जाए, तो आपको फिर इसमें एक्सपर्ट की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कहना है डायटिशन प्राची का। वह कहती हैं कि एक्सपर्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि क्योंकि इस डायट को शुरू करने से 2-3 पहले से ही आपकी नॉर्मल डायट में बदलाव लाना शुरू करना पड़ता है।

कीटो डायट के साइड इफेक्ट्स

डायटिशन प्राची कहती हैं, कीटो डायट के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बॉडी को किटॉसिस पर जाने में 4-5 दिन लगते हैं। तो हो सकता है कि इस दौरान आप थकान फील करें। लेकिन एक बार बॉडी इस डायट पर चली जाएगी, तो आप सुबह से शाम तक एनर्जेटिक फील करेंगी। वह कहती हैं कि यह डायट ओवरऑल आपको ग्लो देती है। चाहे बाल हों या स्किन। इस डायट से वजन काफी जल्दी कम होता है। कलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर सही रहता है। ज्यादा भूख नहीं लगती और एकाग्रता बढ़ती है।

कीटो डायट में इन चीजों को शामिल करें

- सीफूड खाएं। सैमन और अन्य मछलियों में विटमिन, पोटैशियम और सेलेनियम होता है जिसमें कार्ब नहीं होता।

- ऐसी सब्जियां जिसमें स्टार्च नही हैं। इनमें कैलरीज और कार्बोहाइड्रेट कम होता है, लेकिन उनकी न्यूट्रिशस वैल्यू बहुत होती है। इसमें ब्रॉकली, फूलगोभी और पत्तागोभी शामिल है।

- चीज को शामिल करें। चीज में कार्ब काफी कम मात्रा में होता है और फैट में हाई होता है। 28 ग्राम शेडर चीज में 1 ग्राम कार्ब और 7 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है।

- ऐवकाडो एक ऐसा फल है जिसमें लगभग 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और कई विटमिन और खनिज के अलावा उच्च मात्रा में पोटैशियम पाया जाता है।

- एक बड़े अंडे में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि केटॉजेनिक डायट के लिए बेस्ट है।

- दही को भी केटॉजेनिक डायट के लिए काफी उपयोगी माना गया है। 150 ग्राम दही में सिर्फ 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 11 ग्राम प्रोटीन होता है।

- इसके अलावा नट्स और सीड्स उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ लो कार्ब की श्रेणी में आते हैं। आप केटॉजेनिक आहार में बादाम, काजू, पिस्ता, चिया बीज, सन बीज आदि भी शामिल कर सकती हैं।

दफ्तर में हो बहुत काम पर नींद करे परेशान, चुटकियों में भागेगी नींद

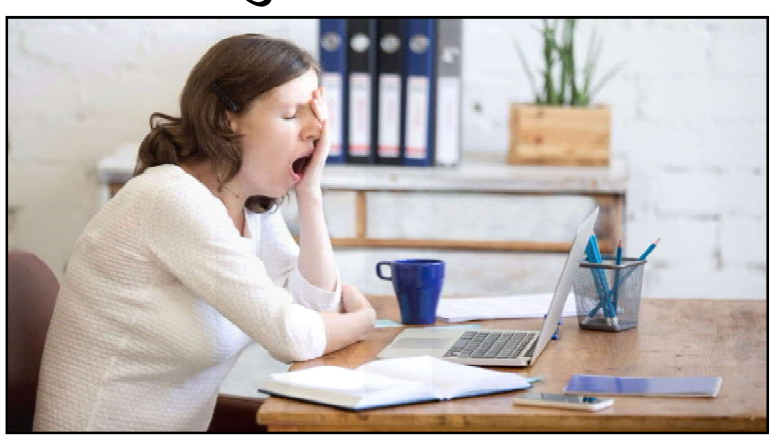

आप दिन के 8 से 10 घंटे दफ्तर में गुजारते हैं, ऐसे में सुस्ती और आलस आना आम बात है, लेकिन कई बार आपकी ये सुस्ती काम पर असर डालती है, जिसका नतीजा आपके लिए बुरा हो सकता है. हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसे टिप्स जिसे अपनाकर आप एक्टिव रह सकते हैं.

पानी एक ऐसी दवा है जो सुस्ती भगाने में बेहद कारगर है, इसलिए जब भी आलस आए, तुरंत पानी पिए ऐसा करने से आपकी सुस्ती झट के गायब हो जाएगी.

अक्सर कम्प्यूटर पर काम करते-करते हाथ थक जाते हैं, इसीलिए अपने हाथों का मूवमेंट करते रहना चाहिए जिससे सुस्ती दूर होती है.

खुली चाय पत्ती या टी-बैग्स, सेहत के लिए कौन-सी चाय है बेस्ट

जब ज्यादा आलस आए तो अपने सीट से उठकर 2 मिनट के लिए टहल लें.

ऑफिस में लंच हल्का करें, क्योंकि ज्यादा हैवी खाने से आलस आता है.

ऑफिस में तरोताजा रहने के लिए जरूरी है पूरी नींद लेना, इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें.

सनग्लास खरीदते हुए कभी न करें ये 5 ग़लतियां, आंखें हो जाएंगी कमज़ोर

गॉगल्स के बारे में आम धारणा है कि जितने डार्क होंगे, उतने ही अच्छे होंगे. ये धारणा सही नहीं है. डार्कनेस का अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव से कोई ताल्लुक नहीं. गर्मियों का मौसम आते ही सनस्क्रीन के अलावा सनग्लास भी जरूरी हो जाते हैं. आंखों की सेहत के लिए धूप में निकलते वक्त ये बहुत जरूरी भी हैं. लेकिन सनग्लास का डार्क होना ही काफी नहीं. कई बार लोग केवल डार्क ग्लास को ही धूप का चश्मा मान लेते हैं. ये आंखों के लिए अच्छा नहीं. ये यूवी रेज़ से आंखों को बचा नहीं पाते और नुकसान भी पहुंचाते हैं.

हम आपको बता रहे हैं कुछ टिप्स, जिनसे आप अपने लिए सही सनग्लासेज का चुनाव कर सकते हैं. धूप का चश्मा ऐसा ही लें, जिनसे आपकी आंखें पूरी तरह से ढंक जाएं. आंखों के लिए यही सही रहते हैं. छोटे सनग्लासेज की अगर डिजाइन पसंद आ रही हो तो ये कभी-कभार थोड़ी देर पहनने के लिए ले सकते हैं. चश्मा वही ठीक रहता है, जो चेहरे पर फिट आ सके, यानी न तो

बहुत ढीला हो और न ही बहुत कसा हुआ. इससे आंखों की सुरक्षा होती है.

कोशिश करें कि सनग्लास ब्रांडेड हों. इनमें अल्ट्रावायलेट किरणों से निपटने की क्षमता होती है. अगर धूप में ज्यादा वक्त बीतता हो तो इसका ख्याल रखना जरूरी है.

बहुत से ग्लासेज कई रंगों में आते हैं. अगर आपके चेहरे पर ये अच्छे लग रहे हैं, आंखों को पूरी तरह से ढंक रहे हैं तो इन्हें लेने में कोई परेशानी नहीं, बशर्ते ये अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन भी देते हों.

आंखें कमजोर हों तो पावर्ड ग्लास लेने की कोशिश करें. इससे आंखों की सुरक्षा होती है और साथ ही देखने में भी कोई परेशानी नहीं होती है.

इन सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए साथ ही सनग्लास लेते हुए चेहरे के शेप का भी ध्यान रखें. इससे आंखों का बचाव तो होता ही है, चेहरे का आकर्षण भी बढ़ जाता है.

दीवारों को दें कैविटी ट्रीटमेंट, घर रहेगा ठंडा

गर्मी में एसी और कूलर के बिना रहा नहीं जाता, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा चला नहीं सकते क्योंकि बिजली का बिल बहुत आता है। लिहाजा हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे तरीके जिसके जरिए बिना एसी और कूलर चलाए भी आप अपने कमरे को कूल रख सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है...

छत को रखें वाइट

गर्मियों में वाइट कलर आंखों को सुकून देने के साथ ही, कूल भी रखता है। यह कलर हीट को कम सोखता है जिससे आधी गर्मी तो वैसे ही कम हो जाएगी। गर्मी के मौसम में छत पर सफेद पेंट या चूनायुक्त सफेद सीमेंट का लेप लगाकर गर्मी के प्रभाव को 70त्न तक कम कर सकते हैं।

सीलिंग पर वेंटिलेशन लेयर ट्रीटमेंट

कमरे की सीलिंग पर वेंटिलेशन लेयर ट्रीटमेंट देकर भी घर को समर फ्रेंडली बनाया जा सकता है। सीलिंग को हमेशा हल्के रंग से रंगना चाहिए। ऐसा ही दीवारों के बाहरी और अंदरूनी हिस्से पर भी करना चाहिए। हल्के रंगों के प्रयोग से घर का तापमान बाहरी तापमान के मुकाबले 1-2 डिग्री कम हो जाता है। कमरे को ठंडा बनाए रखने के लिए लाइट ब्लू शेड का इस्तेमाल सबसे सही रहता है। नीला रंग हीट कम सोखता है और ठंडक बनी रहती है।

दीवारों को दें कैविटी ट्रीटमेंट

आजकल घर बनवाते वक्त कई ऐसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जिससे घर की दीवारें गर्मी में भी ठंडी रहती हैं। इनमें से एक है कैविटी ट्रीटमेंट। इसमें दीवारों के बीच गैप रखा जाता है। इससे घर पर सीधी धूप पड़ती भी है तो वह पहली दीवार पर रुक जाती है। इसके अलावा सीलन, नमी जैसी दिक्कतें भी नहीं होती।

एसीसी ब्रिक्स

एसीसी ब्रिक्स के इस्तेमाल से भी गर्मी में घर ठंडा रहता है। यह नॉर्मल ईंट से चार गुना बड़ी होती है। यह ईंट हीट को रिफ्लेक्ट और पानी को अब्जार्व करती है। साउथ और वेस्ट की दीवारों पर ज्यादातर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट की तुलना में साउथ और नॉर्थ की तरफ से ज्यादा धूप आती है।

वॉटर बेस्ड पेंट का करें प्रयोग

आजकल घरों में ज्यादातर ऑयल-बेस्ड पेंट करवाने का ट्रेंड है, जो काफी महंगा भी होता है, लेकिन इससे कमरे का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को कम रखने के लिए वॉटर बेस्ड पेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। वॉटर बेस्ड पेंट हीट को रिफ्लेक्ट करता है।

डेकोरेशन में यूज करें लाइट कलर

दीवारों का रंग बदलने के साथ इंटीरियर में कई ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे आंखों को ठंडक मिले। पिक्चर फ्रेम में अपने हॉलिडे और वीकेंड के इंजॉयफुल फोटोज ऐड करें। इसके अलावा सीजनल प्लांट्स घर के कोनों में रखें।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में सूचना-विश्वास के संघर्ष का दौर

देश की राजधानी दिल्ली की हल्की सर्दियों में 16 नवंबर 2025 की दोपहर जब नेशनल मीडिया सेंटर मै अपनी उपस्थित दर्ज का मौका मिला पी सी आई के विशेष आमंत्रित मीडिया कर्मी के रूप में। हालॉकि हम जैसे मान्यता प्राप्त मीडिया मित्रों के लिय नेशनल मीडिया केन्द सुचना व कार्य स्थल पर हम अवसर जाते रहते है। आज का यह सिर्फएक औपचारिक समारोह नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक-प्रेस की स्वतंत्रता का राष्ट्रीय उत्सव था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस,जो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना का प्रतीक है, इस वर्ष एक ऐसे समय में आया जब दुनिया भर में समाचारों की गति, सत्यता और विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तकनीक के तीव्र बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विस्फोटक गति और सोशल मीडिया के अनियंत्रित प्रवाह ने सूचना को हथियार भी बना दिया है और भ्रम भी। ऐसे समय में प्रेस की भूमिका एक प्रहरी की है ,यह प्रहरी तभी प्रभावी हो सकता है जब उसकी स्वतंत्रता के साथ उसकी विश्वसनीयता भी अक्षुण्ण रहे। इस वर्ष के राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम स्पष्ट और समकालीन थी बढ़ती गलत सूचना के दौर में प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा। यह विषय जितना आवश्यक है,उतना ही चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि आज की सूचना-प्रणाली वही नहीं है जो दस वर्ष पहले थी। आज खबरें न सिर्फ कई गुना तेजी से चलती हैं, बल्कि उनकी सच्चाई को चुनौती देने वाले साधन भी दस गुना शक्तिशाली हो चुके हैं।ए आई निर्मित सामग्री, डीपफेक, एल्गोरिद्म आधारित इकोदृचौंबर्स और ट्रेंडदृचालित खबरों ने पत्रकारिता को एक नई नैतिक परीक्षा के सामने खड़ा कर दिया है। नेशनल मीडिया सेंटर का सभागार उस दोपहर कुछ आमंत्रित सदस्यों के रूप मेंपत्रकारों, संपादकों, मीडिया छात्रों और वरिष्ठ संचार विशेषज्ञों से भरा हुआ था। मंच पर देश के प्रतिनिधि के प्रमुख हस्तियाँ मौजूद थे। जन-संचार की उभरती चुनौतियों पर होने वाला यह संवाद जितना विशिष्ट था, उतना ही प्रासंगिक भी। इस मंच की गरिमा बढ़ा रहे थे प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई, प्रेस ट्रस्ट ऑफइंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय जोशी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।कार्यक्रम का प्रारंभ इस स्वीकारोक्ति के साथ हुआ कि प्रेस लोकतंत्र की आँख और कान है।यह वही संस्था है जो सत्ता की गतिविधियों पर निगाह रखती है, नागरिकों की आकांक्षाओं को स्वर देती है और समाज को सचेत करती है। लेकिन बदलते समय में इस भूमिका पर अभूतपूर्व दबाव है, क्योंकि सूचना की दुनिया अब मनुष्यों से अधिक मशीनों द्वारा संचालित होने लगी है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता यही है कि खबरों की सच्चाई मशीन के कोडों में कहीं विलुप्त न हो जाए और पत्रकार का नैतिक विवेक एल्गोरिद्म के आगे झुक न जाए। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने अपने संबोधन में यही चिंता और आशा दोनों को बड़ी सहजता से व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, एआई कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, मानव मस्तिष्क की जगह वह कभी नहीं ले सकता। निर्णय, संवेदना और जिम्मेदारीकृये तीन तत्व पत्रकारिता की आत्मा हैं,और इनका उद्गम मशीनों में नहीं, मनुष्यों में है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रेस परिषद का दायित्व दोहरा है, एक तरफप्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा तो दूसरी तरफ पत्रकारिता के आचार संहिता की मर्यादा को बनाए रखना। दोनों में संतुलन रखना ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। उन्होंने बताया कि प्रेस परिषद ने हाल के वर्षों में कई समितियाँ और फैक्ट-फाइंडिंग टीमें गठित की हैं, जो पत्रकारिता में गलत प्रवृत्तियों, दुष्प्रचार, दुरुपयोग और दमनकारी स्थितियों की जाँच करती हैं। उनका कहना था कि पत्रकारों की वित्तीय सुरक्षा भी प्रेस के स्वस्थ भविष्य का हिस्सा है। यदि पत्रकार लगातार आर्थिक तनाव या असुरक्षा से जूझेगा तो उसका मनोबल और स्वतंत्रता दोनों प्रभावित होंगी। इसलिए,कल्याण योजनाओं और बीमा सुरक्षा को मजबूत करना भी पत्रकारिता की जिम्मेदारी का ही एक घटक है। उनका वक्तव्य जितना संतुलित था,उतना ही चेतावनीपूर्ण भी। उन्होंने कहा कि ए आई के बढ़ते उपयोग ने कई सुविधाएँ दी हैं, डेटा खोजने से लेकर कंटेंट विश्लेषण तक, लेकिन इसका अंधाधुंध उपयोग नुकसानदेह हो सकता है। पत्रकारों को तथ्यदृजांच और सत्यापन को सर्वोपरि रखना होगा,चाहे मशीनें कितनी भी तेज और सुविधाजनक क्यों न लगें। माहौल तब और विचारोत्तेजक हुआ जब पी टी आई के सीईओ विजय जोशी ने अपना मुख्य संबोधन दिया। उनका भाषण न केवल सटीक विश्लेषण से भरा था,बल्कि पत्रकारिता के नैतिक आधार को फिर से जीवित कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि आज समाज एक इन्फोडेमिक का सामना कर रहा है, जानकारी इतनी अधिक है कि उसमें सत्य को ढूँढ़ना कठिन हो गया है। ऐसे में उनकी एक पंक्ति पूरे सभागार के हृदय में उतर गई, पारंपरिक मीडिया में गति से अधिक सटीकता को महत्व दें, और डिजिटल मीडिया में एल्गोरिद्मदृआधारित लोकप्रियता की जगह विश्वसनीयता को प्राथमिकता बनाएं। कटु किंतु सत्य बात कही कि पीत पत्रकारिता, पेड न्यूज और एजेंडादृचालित रिपोर्टिंग ने जनता के विश्वास को भारी क्षति पहुँचाई है। पत्रकारिता का मूल तत्वकृनिष्ठा, निष्पक्षता और सत्यकृआज चुनौती के घेरे में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेस की यह जिम्मेदारी है कि वह लोकतंत्र का प्रहरी बने,न कि किसी पक्ष का प्रचारक।पत्रकारिता न तो सत्ता की ताली बजाए और न विपक्ष का शंख फूँके। उसकी भूमिका सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेही की होनी चाहिए। विजय जोशी ने पी टी आई की इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया कि यह संस्था 99 समाचार पत्रों द्वारा स्थापित की गई थी और तब से आज तक सत्य, स्वतंत्रता और न्यायसंगत रिपोर्टिंग को ही अपना मूल मंत्र मानती आई है। आज जब डिजिटल मीडिया सच और झूठ को समान गति से आगे बढ़ा देता है,तब पत्रकारों के लिए दोहरा दायित्व हैकृपहले तथ्य की शुचिता सुनिश्चित करना और दूसरा, अपने पाठकों-दर्शकों को एल्गोरिद्म के भ्रमित जाल से सुरक्षित निकालना। उन्होंने पत्रकारिता के विद्यार्थियों और नए रिपोर्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में सिर्फवही पत्रकार सफल होगा जो नैतिकता और आलोचनात्मक सोचकृदोनों में निपुण होगा। यह कौशल मशीनें कभी नहीं दे सकतीं। सत्य की रक्षा मानव विवेक ही कर सकता है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही,हालांकि उन्होंने मंच से भाषण नहीं दिया। बाद में लंच के दौरान जब कुछ टीवी चौनलों ने उनसे प्रतिक्रिया चाही,तो उन्होंने संक्षिप्त टिप्पणी में यही कहा कि मीडिया क्षेत्र में तेजी से बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सरकार सरलीकृत, पारदर्शी और तकनीक, आधारित प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल और पी आर पी एक्ट 2023 का उल्लेख कर बताया कि अब पंजीकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अधिक सुलभ और डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। मंत्री की प्रतिक्रिया भले संक्षिप्त थी, लेकिन उसमें यह संकेत था कि तकनीक और नैतिकता दोनों साथ साथ चलें, ऐसा ढाँचा तैयार करना समय की माँग है। कार्यक्रम के अंत में प्रेस परिषद की भूमिका और इतिहास पर संक्षिप्त चर्चा हुई। सर्व विदित रहें कि यह संस्था 1966 में संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य था प्रिंट मीडिया के लिए एक स्व-नियमन तंत्र स्थापित करना जो पत्रकारिता को सशक्त भी करे और अनुशासित भी। बाद में 1979 में इसे पुन: स्थापित किया गया और तब से यह संस्था पत्रकारिता में गुणवत्ता और स्वतंत्रता दोनों की रक्षा में एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ बनकर खड़ी है। प्रेस परिषद ने कई बार सरकारों को सलाह दी, मीडिया संस्थानों को चेताया, और पत्रकारों की स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। कार्यक्रम का समापन किसी औपचारिक घोषणा से अधिक एक सामूहिक संकल्प की तरह हुआ। पत्रकारिता को अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए न केवल तकनीकी कौशल बल्कि नैतिक दृढ़ता और मानवीय संवेदना की भी आवश्यकता है। एआई के इस युग में जहाँ सूचना एक क्लिक में उपलब्ध है,वहीं गलत सूचना भी बिजली की गति से फैलती है। ऐसे में पत्रकार को सिर्फखबरें नहीं लिखनी हैं, बल्कि सत्य की रक्षा, समाज का मार्गदर्शन और लोकतंत्र की आत्मा की सुरक्षा भी करनी है।2025 का राष्ट्रीय प्रेस दिवस एक चेतावनी भी था और प्रेरणा भी, चेतावनी इस बात की कि यदि पत्रकारिता ने अपना चरित्र खो दिया, तो सूचना का भ्रम लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देगाय और प्रेरणा इस बात की कि सत्य की लौ जलाए रखने वाले पत्रकार हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मानव विवेक और नैतिक पत्रकारिता ही लोकतंत्र को टिकाए रख सकते हैं। सत्य, सटीकता और विश्वसनीयता का यह संग्राम आगे भी जारी रहेगा और प्रेस परिषद, मीडिया संस्थान तथा पत्रकार समाज मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे।

बिहार जीत से उभरी नई उम्मीदें और गहरी चुनौतियों

बिहार का यह चुनाव केवल एक राजनीतिक मुकाबला नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की चेतना, जनता के विश्वास और नेतृत्व की विश्वसनीयता को परखने का अवसर भी था। परिणाम जिस तरह सामने आए, उन्होंने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश एवं दुनिया को चौका दिया। यह जीत केवल गठबंधन की सामूहिक ताकत की नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्षों से स्थापित सुशासन मॉडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के अटूट भरोसे का परिणाम है। बिहार की महिलाओं ने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई है-उनकी उम्मीदें, उनका साहस और उनका भरोसा इस परिणाम के मूल में खड़ा दिखाई देता है। बिहार में इतने एकतरफा नतीजे की उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। चुनाव प्रचार के दौरान जो लड़ाई टक्कर की दिख रही थी, वह आखिर में केवल भ्रम साबित हुई।

जनता ने न महागठबंधन के बदलाव के नारे पर यकीन किया और न ही प्रशांत किशोर की अलग राजनीति पर भरोसा जताया, बल्कि खुद को परिपक्व एवं जागरूक प्रदर्शित करते हुए मूल्यों एवं विकास के मानकों पर मतदान दिया। आंकड़ों का विश्लेषण होता रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर यह परिणाम कई संदेश देता है कि अब बिहार जंगलराज नहीं चाहता, विकास की नई सुबह देखना चाहता है, एसआईआर को वोट चोरी के रूप में दी गयीप्रस्तुति उसे स्वीकार्य नहीं हुई, वह अतीत के भ्रष्ट शासन से मुक्ति के लिये अतीत की त्रासद यादों एवं भविष्य के सुनहरे भविष्य के बीच चयन करते हुए लालू-राबड़ी यादव के शासनकाल की की काली छाया नहीं चाहता। भले ही तेजस्वी यादव पूरे समय इसी नैरेटिव को तोड़ने में लगे रहे कि वक्त बदल चुका है और वह दौर अब नहीं लौटेगा। उन्होंने उल्टे अपराध पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की, पर सफल नहीं रहे।

नीतीश कुमार के लिए 20 बरसों में यह पहला विधानसभा चुनाव था, जहां वह गठबंधन का तो चेहरा थे, पर सीएम पद के उम्मीदवार नहीं थे। उनकी छवि को धुंधलाने एवं उन्हें बीमार घोषित करने के भी पूरे प्रयत्न हुए लेकिन, परिणाम ने साबित किया है कि नीतीश अब भी बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीक एवं सुशासन-पुरुष हैं। वह अब तक नौ बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, कई बार उन्होंने पाला बदला, लेकिन जनता का यकीन उन पर बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह उनकी बेदाग छवि भी है। लेकिन इस बार उनकी चुनौतियां भी बड़ी है। वैसे लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जीत जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां भी उतनी ही व्यापक हो जाती हैं। बिहार में एनडीए की इस ऐतिहासिक विजय के बाद जिस दौर की शुरुआत हो रही है, वह उत्साह से कहीं अधिक जिम्मेदारी का दौर है। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यह अपने-आप में निरंतरता, स्थिरता और सुशासन की अपेक्षाओं को नयी ऊँचाई देता है। परंतु अब उनके सामने जो प्रश्न खड़े हैं, वे कहीं अधिक गहरे, जटिल और चुनौतीभरे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार केवल एक राजनीतिक पराजय नहीं, बल्कि परिवारवादी राजनीति के प्रति जनता की निर्णायक और स्पष्ट निष्पत्ति है। मतदाताओं ने यह संदेश दो टूक दिया है कि राजनीति किसी परिवार, वंश या व्यक्तिगत प्रभुत्व की जागीर नहीं हो सकती। खासकर क्षेत्रीय दलों में फैला वंशवाद, व्यक्तिवाद और उत्तराधिकार की अनिवार्य राजनीति जनता को लगातार विचलित करती रही है। परिणामों ने यह उजागर कर दिया कि अब मतदाता सिर्फ चेहरे और परिवारों के मोहजाल में नहीं फँसना चाहते, बल्कि वे विकास, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को प्राथमिकता देने लगे हैं। महागठबंधन की हार उसी व्यापक जनभावना का परिणाम है, जिसमें जनता ने यह तय कर दिया कि लोकतंत्र में जनता की सत्ता सर्वोपरि है, किसी भी राजनीतिक खानदान की नहीं। बिहार की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। वर्षों से यह राज्य बेरोजगारी के दर्द से जूझता रहा है। करोड़ों युवाओं की आंखों में नौकरी, अवसर और सुरक्षित भविष्य का सपना है। चुनावी वादे जिस उत्तेजना के साथ किए जाते हैं, उन्हें व्यवस्थित नीति, धैर्य और राजनीतिक ईमानदारी से लागू करना किसी भी सरकार के लिए आसान कार्य नहीं होता। लेकिन जनता ने इस बार उम्मीदों की जो गठरी सौंपी है, वह स्पष्ट संकेत है कि अब पूरा बिहार ठोस काम चाहता है, खोखले वादे नहीं। दूसरी बड़ी चुनौती कानून-व्यवस्था की है। सुशासन का मॉडल तभी सार्थक है जब आम नागरिक के जीवन में सुरक्षा की ठोस अनुभूति हो। अपराध, राजनीतिक संरक्षण, दंगा-फसाद और अराजकता किसी भी समाज की प्रगति को रोकते हैं। नीतीश कुमार से जनता की अपेक्षा है कि वे एक बार फिर वही कठोरता, वही व्यवस्था और वही संतुलित रणनीति लेकर आएंगे, जिसने कभी 'जंगलराज' को समाप्त कर सुशासन का नया इतिहास लिखा था। महिलाओं से किए गए वादे भी अब सरकार की प्राथमिक कसौटी बनेंगे। आधी आबादी ने जिस उत्साह और भरोसे के साथ एनडीए को पुन: सशक्त किया है, यह सरकार के लिए प्रेरणा के साथ-साथ उत्तरदायित्व भी है। सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान-ये पांच मुद्दे बिहार की महिलाओं की असली जरूरत हैं, और चुनावी वादों का मूल्यांकन भी अब इन्हीं पर होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था की मजबूती केंद्र सरकार के सहयोग पर भी निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके विकास-एजेंडे ने इस चुनाव को निर्णायक रूप दिया। जब केंद्र और राज्य की नीतियों में तालमेल होगा, तब ही आर्थिक सुधार, निवेश, उद्योग, रोजगार-सृजन और आधारभूत संरचना के बड़े सपने साकार होंगे। बिहार को अब केवल वित्तीय सहायता की ही नहीं, बल्कि विकास की स्थायी संरचना की जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित हों। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा प्रश्न मन को झकझोरता है-लोकतंत्र में चुनाव कब तक केवल 'सौदेबाजी' बने रहेंगे? कब तक वादों की भीड़, लुभावने नारों और जातीय समीकरणों के आधार पर जनता के विश्वास की खरीद-फरोख्त चलती रहेगी? आखिर लोकतंत्र की स्वस्थ दिशा क्या हो? यह चुनाव परिणाम हमें इस सवाल के सामने खड़ा करता है कि राजनीति को फिर से मूल्यों, दृष्टि, दीर्घकालिक योजनाओं और नैतिकता की ओर लौटना होगा। लोकतंत्र की प्रतिष्ठा तभी बचेगी जब राजनीति भविष्यदर्शी बने, जब चुनाव उत्सव कम और उत्तरदायित्व अधिक हों। बिहार, जिसे कभी पिछड़ेपन, गरीबी, पलायन और अपराध का प्रदेश कहा जाता था, आज भारतीय लोकतंत्र का एक जीवंत प्रयोगशाला बन गया है। यह केवल सत्ता की नीतियों पर ही नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता, मीडिया की ईमानदारी और राजनीतिक दलों की नैतिक प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करेगा। आज बिहार के पास अवसर है कि वह खुद को एक प्रगतिशील, शिक्षा-संपन्न, रोजगार-समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करे।

बारात से लौट रहा वाहन खाई में गिरा, दो की मौत, तीन घायल

हमारे संवाददाता

चमोली। बारात से लौट रहे वाहन के खाई में गिर जाने से खुशिया मातम में बदल गयी। इस हादसे में जहां दो लोगों की मौत हो गयी वही तीन लोग गम्भीर रूप से घायल हुए है। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनो शवो को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

सड़क हादसे का यह मामला हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर हुआ है। पुलिस के अनुसार बीती शाम के समय हेलंग उर्गम मार्ग पर पावर हाउस के पास बरातियों का वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। दुर्घटना की सूचना पर ज्योतिर्मठ से पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान चलाने में दिक्कतें हुईं। दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो घायलों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला गया। दुर्घटना में ध्रुव (19) पुत्र कुशल और कन्हैया (20) पुत्र धीरेंद्र, दोनों निवासी सलूड़ ज्योर्तिमठ की मौके पर ही मौत हो गई है। एसडीएम ज्योतिर्मठ चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि दूल्हे के पिता मनवर सिंह निवासी सलूड़ ने बताया

कि गाड़ी में पांच लोग सवार थे। दो की मौत हो गई और तीन घायल हुए हैं। घायलों में पूरण सिंह (55) निवासी सलूड़ ज्योर्तिमठ, कमलेश (25) पुत्र मुरली निवासी पल्ला ज्योतिर्मठ और मिलन (28) पुत्र मनवर निवासी सलुड़ शामिल हैं। पूरण को गंभीर चोटें आने पर गोपेश्वर रेफर कर दिया गया है।

एसएसपी ने थाना घनसाली का किया औचक निरीक्षण

संवाददाता

टिहरी। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने थाना घनसाली का औचक निरीक्षण कर नवनिर्मित थाना भवन की गुणवत्ता का भी जायजा लिया।

जनपद टिहरी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल द्वारा आज थाना घनसाली के थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिस दौरान नवनिर्मित थाना भवन का भी गहन निरीक्षण किया गया। इस भवन की प्रगति और गुणवत्ता को परखा गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी द्वारा निर्माण सामग्री, दीवारों की प्लास्टरिंग, विद्युत एवं स्वच्छता व्यवस्थाओं सहित भवन की संपूर्ण संरचना का बारीकी से परीक्षण किया गया। उन्होंने निर्माण कार्यों में लग रहे मजदूरों व इंजीनियरों से भी वार्ता कर वर्तमान स्थिति, समयख्रसीमा तथा कार्य की गुणवत्ता संबंधी जानकारियाँ लीं। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि थाना भवन पुलिस कार्यक्षमता और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखकर आधुनिक मानकों के अनुरूप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित भवन भविष्य में पुलिस और जनता के लिए एक सुरक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम एवं सुविधाजनक वातावरण प्रदान करेगा। निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, उपयोग हो रही सामग्री उच्च गुणवत्ता की हो। सुरक्षा मानकों, भूकंपीय संवेदनशीलता तथा टिकाऊ निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाए। आयुष अग्रवाल, वरिष्ठ

नवनिर्मित थाना भवन की गुणवत्ता का भी लिया जायजा

पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा निरीक्षण के दौरान पुलिसिंग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने हेतु आज थाना घनसाली का औचक निरीक्षण किया गया। एसएसपी ने थाना परिसर की स्वच्छता, अभिलेखों के रख-रखाव, आगंतुक रजिस्टर, मालखाने व हथियारागार की स्थिति को परखा। उन्होंने अभिलेखों को अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। थाना घनसाली पर उपस्थित फरियादियों की समस्याओं को स्वयं सुना तथा उनकी शिकायतों के त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण हेतु थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक फरियादी थाना स्तर पर सम्मानजनक व्यवहार और त्वरित सहायता का हकदार है। बीट व्यवस्था एवं गश्त की समीक्षा एसएसपी महोदय ने बीट प्रणाली, पेट्रोलिंग पॉइंट्स और क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की निगरानी तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी ली। बेहतर गश्त व्यवस्था एवं रात्रि गश्त को और मजबूत करने के निर्देश दिए। कर्मचारियों की ड्यूटी, अनुशासन एवं वर्दी की जांच निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की उपस्थिति, वर्दी, अनुशासन एवं व्यवहार की जांच की गई। उन्होंने कहा कि अनुशासन ही पुलिस व्यवस्था की रीढ़ है और इसे हर परिस्थिति में सर्वोपरि रखना आवश्यक है।

चरस के साथ दो गिरफ्तार, वाहन सीज

संवाददाता

टिहरी। पुलिस ने चरस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित "ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025" के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में नशा विरोधी अभियान को प्रभावी बनाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर के निकट पर्यवेक्षण में मादक पदार्थों की तस्करी एवं परिवहन के विरुद्ध थाना नरेन्द्रनगर पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में थाना नरेन्द्रनगर क्षेत्रान्तर्गत प्लास्डा बैरियर पर वाहनों की सघन चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान एक कार अल्टो को रोककर जांच की गई। वाहन में सवार दो व्यक्तियों के कब्जे से कुल 678 ग्राम चरस बरामद हुई। मौके पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम सतेन्द्र सिंह रावत, पुत्र सुरेन्द्र सिंह रावत निवासी ग्राम धारकोट, पोस्ट बनचौरा, थाना धरासू, जनपद उत्तरकाशी, सुभाष रावत, पुत्र इतेन्द्र सिंह रावत निवासी ग्राम बनगांव, पोस्ट बनगांव, थाना धरासू, उत्तरकाशी बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया।

टिहरी डैम सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही के लिए खुला

देहरादून। टिहरी डैम टॉप पर सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी गयी है। आज यहां उप महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासनिक माहेन सिंह ने कमाडेण्ट सीआईएसएफ, जिला अधिकारी टिहरी, मुख्य महाप्रबंधक टिहरी काम्पलेक्स को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि टीएचडीसी द्वारा 12 नवम्बर 2025 को सुरक्षा की दृष्टि से टिहरी डैम टॉप पर सार्वजनिक वाहनो की आवाजाही बंद करने का निर्णय लिया गया था। उसके अनुक्रम में अवगत कराना है कि 20 नवम्बर से सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही को पूर्ववत बहाल किया जाने का निर्णय लिया गया है।

लखवाड व्यासी परियोजना सीएम की प्राथमिकता में से एक है: डीएम

संवाददाता

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल ने कहा कि लखवाड़ व्यासी परियोजना राज्य देश तथा मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में से एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में हम सबकी भूमिका अत्यंत गहन है।

आज यहां जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में लखवाड़-व्यासी जल विद्युत परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना से प्रभावित हितधारकों, संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने बैठक में परियोजना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लखवाड़ व्यासी परियोजना राज्य देश तथा मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में से एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में हम सबकी भूमिका अत्यंत गहन है। जिलाधिकारी ने मुआवजा वितरण की प्रगति प्रभावित परिवारों को देय भूमि, भवन एवं अन्य परिसंपत्तियों के मुआवजे के वितरण की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए की मुआवजे अनुग्रह राशि का भुगतान टाइमबांड करें। साथ ही निर्देशित किया जिन सम्पत्तियों के मूल्यांकन नही हुआ है अथवा प्रभावितों को आपत्ति है तो शिड्यूल निर्धारित करते हुए परिसम्पतियो का मूल्यांकन किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी स्थानीय स्तर पर सप्ताह में 01 दिन कैम्प लगाकर 1 छत के नीचे बैठकर आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। प्रभावितों ने अनुरोध किया कई परिवार ऐसे हैं जिनका वर्ष 2023 मार्च से पूर्व पृथक थे तथा पोर्टल पर आनलाईन मार्च 2023 के उपरान्त अद्यतन हुए जिनको 2023 के उपरान्त पृथक परिवार माना जा रहा है जिससे मुआवजा में पात्र नही हो पा रहे जिस पर जिलाधिकारी प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की बात कही। जिलाधिकारी ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों के मुआवजे का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी एवं अचल परिसंपत्तियों के आकलन के कार्य कैम्प लगाकर परिसंपत्ति मूल्यांकन पूर्ण पारदर्शिता के साथ तेजी से पूरा कराया जाए ताकि भुगतान प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की देरी न हो। प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को समस्त वित्तीय सहायता तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना की राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व को देखते हुए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें। बैठक में उपस्थित प्रभावितों ने मुआवजा, स्थानांतरण, पुनर्वास तथा अन्य स्थानीय मुद्दों से संबंधित अपने सुझाव व समस्याएँ जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी प्रक्रियाएँ नियमों के अनुरूप और पारदर्शी ढंग से संचालित की जाएंगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि लखवाड़-व्यासी जल विद्युत परियोजना राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, और इसके सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम निरंतर उठाए जाते रहेंगे। बैठक में अपर जिलाधिकारी के.के मिश्रा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, आईएम कराती जीएम यूजीवीएनएल, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओपी सिंह, लाखामंडल जलकल्याण समिति जगमोहन सिंह चौहान, महासचिव स्वराज सिंह तोमर, अन्य प्रभावित व सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिवक्ताओं की हडताल दसवें दिन भी जारी

संवाददाता

देहरादून। चेम्बर निर्माण की मांग को लेकर हडताल पर चल रहे अधिवक्ताओं का विरोध दसवें दिन भी जारी रहा।

आज यहां चेम्बरों सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन दसवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान अधिवक्ता हरिद्वारा रोड पर ध रने पर बैठे रहे। इस दौरान वकीलों के चेंबर निर्माण और जमीन आवंटन की मांगों को लेकर देहरादून बार एसोसिएशन और सरकार के बीच कोई समन्वय नहीं बन सका है। एसोसिएशन की ओर से गठित संघर्ष समिति ने सरकार के सामने अपनी मांगे रख दी हैं। इस सूरत में आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अदालत के साथ-साथ रजिस्ट्रार ऑफिस का काम भी ठप पड़ा है। हड़ताल के चलते बस्ते, टाइपिंग, स्टाम्प वेंडर आदि सेवाएं भी पूरी तरह बंद हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव राजबीर सिंह बिष्ट ने सभी अधिवक्ताओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए अनिवार्य उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि सभी अधिवक्ता अदालत और न्यायिक कार्यालयों से पूरी तरह विरत रहेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस में भी काम नहीं

होगा। समिति ने भवन निर्माण और भूमि आवंटन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करके प्रशासन के सामने रखे है। प्रशासन की ओर से दिए जाने वाले आश्वासन, फैसले या घोषणाएं लिखित में और समयबद्ध तरीके से ही स्वीकार्य होंगी। नई जिला अदालत में आवंटित भूमि के साथ पुरानी जिला अदालत की संपूर्ण भूमि को अधिवक्ता चैंबर व भवन निर्माण के लिए आवंटित करने की मांग रखी है, जिसका उपयोग सभी वकील, मुंशी, टाइपिस्ट, स्टाम्प विक्रेता और विधि व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों के बैठने, पार्किंग, कैंटीन, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम और वॉशरूम आदि की सुचारु व्यवस्था के लिए किया जाएगा। नई और पुरानी अदालत को जोड़ने के लिए अंडरपास बनाने की मांग है, क्योंकि दोनों के बीच सड़क पार करना मुश्किल होता है, हादसों का डर रहता है और यातायात भी बाधि त होता है। सभी चेंबर, भवन और अंडरपास का निर्माण कार्य सरकार अपने खर्च पर अपनी सरकारी एजेंसी के माध्यम से करवाए। निर्माण की देखरेख व निगरानी बार एसोसिएशन की ओर से नियुक्त समिति करेगी। सरकार निर्माण संबंधी सभी महत्वपूर्ण फैसलों में इस संघर्ष समिति के सदस्यों को शामिल करेगी। धरने के दौरान धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अत्यंत अफसोस की बात है कि राज्य की राजधानी जहां मुख्यमंत्री, समेत पूरी सरकार है, राज्यपाल व मुख्य सचिव समेत पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है वहां के अधिवक्ता पिछले दस दिनों से एक ऐसे मुददे पर जो पूरी तरह से वाजिब है चैंबर निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं उनकी सुनवाई सरकार गम्भीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक बात है कि अदालों बन गयी पर अदालतों में पैरवी करने वाले अदालत के अधिकारी यानि वकील उनके बैठने का इंतजाम सरकार ने नहीं किया। धस्माना ने कहा कि बिना वकील के अदालत कैसी। उन्होंने कहा कि होना तो यह चाहिए था कि जब जिला न्यायालय का परिसर यह बनना शुरू हुआ था उसी वक्त अदालतों के निर्माण के साथ वकीलों के चैंबर भी बनने चाहिए थे किंतु ऐसा नहीं हुआ और आज जब नए परिसर से सारी अदालतें नए परिसर में आ गयी ऐसे में अधिवक्ताओं को पुराने परिसर से सडक पार कर नए परिसर में आना पडता है। उन्होंने कहा कि यह बात भी समझ से परे है कि पुराने परिसर में पैंसठ बीघा में बैठे अधिवक्ता के चैंबर पांच बीघा जमीप पर कैसे बनेंगे इसलिए सरकार को चाहिए कि पुराने परिसर का एक भाग वकीलों के चैंबर के लिए आवंटित किया जाये और पुराने व नए परिसर को जोडने के लिए अंडरपास का निर्माण किया जाये। जिसके पश्चात सूर्यकांत धस्माना के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गयी।

अवैध खनन रोकने पर वन कर्मी के साथ मारपीट

देहरादून(संवाददाता)। अवैध खनन रोकने पर वन कर्मी से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन सुरक्षाक कर्मी काक्का ने सहसपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि एक ट्रेक्टर सवार कमल पुत्र रामलाल निवासी जाटोवाला डांडीपुर के द्वारा बिना रवन्ने के ट्रेक्टर में खनिज भरकर ले जा रहा था उसने जब उसको रोका तो कमल ने उसके साथ मारपीट करते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचायी और खनिज से भरा ट्रेक्टर लेकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

झाडियों में मिला नवजात शिशु

देहरादून(संवाददाता)। झाडियों में नवजात के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। पुलिस ने नवजात को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहसपुर थाने में तैनात एसएसआई विकास रावत ने सहसपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि टीचर्स कालोनी में शिव मंदिर के सामने जाने वाली रोड पर आगे करीब 600 मीटर पर खाली प्लाट में छोटी झाडियों के बीच एक नवजात शिशु होने की सूचना मिली जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच शिशु को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

शराब के साथ गिरफ्तार

देहरादून(संवाददाता)। पुलिस ने शराब के साथ एक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने परशुराम चौक के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 42 पव्वे शराब के बरामद कर लिये। पूछताछ में उसने अपना नाम सन्नी पुत्र होशियार निवासी गोविन्द नगर झुग्गी झोपडी बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार

देहरादून(संवाददाता)। पुलिस ने स्मैक के साथ महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने बंजारावाला के पास एक महिला को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडी हुई। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 11.29 ग्राम स्मैक बरामद कर ली। पूछताछ में उसने अपना नाम सावली नाथ पत्नी आलम नाथ निवासी सपेरा बस्ती मोथरोवाला बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

पांच पेटी शराब सहित तस्कर गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

चम्पावत। पहाड़ो में शराब तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से पांच पेटी अंग्रेजी शराब व तस्करी में प्रयुक्त वाहन बरामद हुआ है।

जानकारी के अनुसार बीती रात थाना लोहाघाट पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में कोई शराब तस्कर अवैध शराब की डिलीवरी हेतू आने वाला है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने क्षेत्र में चैकिग अभियान चला दिया। इस दौरान पुलिस को बर्दाखान बाराकोट क्षेत्र में एक संदिग्ध आल्टो कार आती हुई दिखायी दी। पुलिस ने जब उसे रूकने का इशारा किया तो कार चालक कार मोड़कर भागने लगा। इस पर उसे घेर कर रोका गया। कार की तलाशी के दौरान उसमें रखी 5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

पूछताछ में उसने अपना नाम पंकज सिंह अधिकारी पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम मटियाल तहसील बाराकोट थाना लोहाघाट बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।

कांग्रेस पार्टी सदैव समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए है प्रतिबद्धः गोदियाल

संवाददाता

देहरादून। आज वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कांग्रेस मुख्यालय पहुंच कर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने पर वाल्मीकि समाज की ओर से पगडी पहनाकर एवं वाल्मीकि तीर्थ का स्मृति चिह्न प्रदान कर स्वागत अभिनन्दन किया गया। वाल्मीकि समाज द्वारा उनको बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सदैव सर्वधर्म समभाव की बात कि है और आगे भी हम इसी भावना को लेकर आगे बढेगें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गो के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि सबल की मदद करने में भले ही विलंब हो जाए परंतु वंचितों का साथ सदैव देना ये कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति है,उन्होने प्रतिनिधि मण्डल को विश्वास दिलाया कि समाज से जुडी समस्याओं एवं सुझावों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। स्वागत सम्मान करने वालो मे वरिष्ठ समाजसेवी कांग्रेस नेता विरेन्द्र पोखरियाल, प्रवक्ता मोहन कुमार काला, आशिष देसाई अध्यक्ष वाल्मीकि सेवा समिति, कैलाश वाल्मीकि, सुरेन्द्र सूद, ओपी वरुण, अनिल बागडी, दीपक पंवार, संजय विरला, नीतिन चंचल, शुभम चंद, मानस चिनालिया, वंश चौधरी एवं करन डबराल आदि लोग मौजूद रहे।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकारः
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालयः दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोटः सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालयहीमान्यहोगा,प्रकाशितसामग्रीके लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।